फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 53 प्रभात जयपुर, बुधवार 23 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

FIBRE-OPTIC DRONES ARE DEFINING CONFLICT

Reports suggest Hezbollah is producing fiber optic drones locally using 3D printing and commercially available dual-use components

I Wasn't Worried!

The Decorated Chest of Tutankhamun

उत्तर प्रदेश के मंत्री राजभर का यूपी विभाजन का प्रस्ताव फिलहाल राजनैतिक मैसेज तक सीमित है

क्योंकि इस मैसेज के जरिए भाजपा को पूर्वांचल जैसे अति पिछड़े क्षेत्रों और अति पिछड़ी जातियों के प्रति संवेदनशील होने का मैसेज देने का अवसर मिलता है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों-पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश-में बांटने की दशकों पुरानी मांग को फिर से चर्चा में ला दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ विशेष रूप से चर्चा की है और दावा किया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जाति जनगणना पूरी होने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। राजभर ने जोर देकर कहा कि नए पूर्वांचल का पहला मुख्यमंत्री राजभर समुदाय से ही होना चाहिए और इसे उन्होंने गठबंधन की एक ऐसी शर्त के रूप में पेश किया, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रैलियों के दौरान दिए गए ये बयान 2027 के विधानसभा चुनावों के करीब आने के बीच सामने आए हैं और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए इन बयानों के स्पष्ट राजनीतिक निहितार्थ हैं।

- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2011 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, तब उन्होंने भी यह प्रस्ताव रखा था, लेकिन केन्द्र सरकार में यह प्रस्ताव अटक गया, बाद में आई सपा सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था।
- यह प्रस्ताव राजनैतिक रूप से ठंडे छींटे भी देता है। इससे यूपी में सरकार विरोधी मुद्दों के बजाय आम जनता में विभाजन पर चर्चा शुरु हो जाएगी और शासन से जुड़े मुद्दे दरकिनार हो जाएंगे।
- यही नहीं, यह प्रस्ताव भाजपा के छोटे सहयोगी दलों को एनडीए में बनाए रखने में भी मददगार हो सकता है।

भाजपा और एनडीए के लिए इस मुद्दे को फिर से उठाने के रणनीतिक फायदे हैं। इससे सत्तारूढ़ गठबंधन को पूर्वांचल में क्षेत्रीय और जातीय आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होने का संदेश देने का अवसर मिलता है, जहां राजभर समुदाय का काफी ज्यादा चुनावी प्रभाव है। इसके लिए, तत्काल कुछ करना भी नहीं है। विभाजन को जाति जनगणना से जोड़कर एनडीए अति पिछड़ा वर्ग के समर्थन को मजबूत कर सकता है और सीट बंटवारे की बातचीत से पहले, एसबीएसपी जैसे छोटे सहयोगियों को गठबंधन में बनाए रख सकता है। इससे सत्ता विरोधी भावना और शासन से जुड़े मुद्दों से भी ध्यान हटता है तथा एनडीए गठबंधन को प्रशासनिक सुधार के लिए तैयार गठबंधन के रूप में पेश करने का अवसर मिलता है। इससे पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों की कथित उपेक्षा को लेकर विपक्ष के आरोपों को भी कमजोर किया जा सकता है। हालांकि, केन्द्र या भाजपा नेतृत्व की ओर से अभी तक इस मांग का कोई आधिकारिक समर्थन नहीं आया है। इससे संकेत मिलता है कि ये दावे ठोस नीति की अपेक्षा, चुनावी मौसम के संदेश जैसे ज्यादा प्रतीत हो रहे हैं।

इस मांग का सीधा संबंध मायावती की 2011 की पहल से है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस विभाजन के लिये कैबिनेट की मंजूरी हासिल की थी और उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश बनाने का प्रस्ताव पारित कराया था और इसके लिए इस विशाल राज्य में बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास का हवाला दिया था। प्रस्ताव कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को भेजा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीबीआई कोर्ट ने बैंक कर्मियों को सात साल की सजा सुनाई

जयपुर, 22 सितंबर। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने लोन राशि बकाया होने के बावजूद एनओसी जारी कर बैंक को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की श्योसिंहपुरा,

- ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की श्योसिंहपुरा लालसोट शाखा के अधिकारियों ने लोन खाते में बकाया होने के बावजूद एनओसी देकर लाखों का नुकसान कराया।

लालसोट, शाखा के तत्कालीन प्रबंधक रामजी लाल मीणा, विशेष सहायक मुरारी लाल मीणा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थान सिंह लश्कर को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों को अर्थदंड से भी दंडित किया है।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि बैंक प्रबंधन ने सीबीआई में 1 फरवरी, 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि बैंक की श्योसिंहपुरा शाखा के तत्कालीन विशेष सहायक मुरारी लाल मीणा ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और तीन लोन खातों में बकाया राशि होने के बावजूद अनाधिकृत रूप से खाताधारकों को एनओसी जारी कर दी। जिससे उन्हें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जल्दी ही ज़मींदोज़ हो जाएंगे दिल्ली के प्रख्यात शास्त्री भवन एवं कृषि भवन

सीपीडब्ल्युडी ने दोनों भवनों को 30 सितम्बर तक खाली करने का नोटिस दिया है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। केन्द्रीय राजधानी के दो प्रतिष्ठित कार्यालय परिसरों, शास्त्री भवन और कृषि भवन, को गिराए जाने की तैयारी है, ताकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों, कर्तव्य भवन 4 और 5, का निर्माण किया जा सके।

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना 'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट' के तहत इन दोनों भवनों को गिराए जाने से वे स्मृतियां भी मिट जाएंगी, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के निकट स्थित शास्त्री भवन से जुड़ी हैं। इस परियोजना को 2019 में मंजूरी दी गई थी और 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी।

लगभग 20,000 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना विवादों में रही है, क्योंकि अन्य भवनों, नए संसद भवन का निर्माण और उद्घाटन हो चुका है, लेकिन उनमें संरचनात्मक खामियां और कमियां सामने आ रही हैं।

सूत्रों ने कहा कि यह फैसला जल्दबाजी को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि मोदी सरकार अगले

- प्रधानमंत्री के प्रिय ड्रीम प्रोजैक्ट सैंट्रल विस्टा के तहत शास्त्री भवन और कृषि भवन को ध्वस्त कर नए कॉमन सैंट्रल सैक्रेटेरिएट भवनों, कर्तव्य भवन 4 एवं 5 का निर्माण किया जाएगा।
- दोनों परिसरों को 30 सितम्बर तक खाली करने का नोटिस दिए जाने से विपक्षी दल प्रोजैक्ट को लेकर जल्दबाजी करने के आरोप भी लगा रहे हैं।
- सीपीडब्ल्युडी द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि दो नए भवनों के निर्माण का टैंडर दिया जा चुका है। इस पर 3,155 करोड़ रूपए की लागत आएगी तथा 12 माह में निर्माण कार्य पूरा करना होगा।

लोकसभा चुनाव से पहले इस परियोजना को पूरा करना चाहती है, क्योंकि इससे भाजपा को यह दावा करने का मौका मिल सकता है कि पार्टी ने एक नई राजधानी का निर्माण किया है।

रिपोर्टों के अनुसार, दोनों परिसरों को 30 सितंबर तक खाली किया जाना है, जिससे इस फैसले की जल्दबाजी पर सवाल उठ रहे हैं।

इस संबंध में सैंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट (सीपीडब्ल्यूडी) ने संबंधित अधिकारियों से सितंबर के अंत तक मौजूदा परिसरों को खाली कर उन्हें सौंपने को कहा है, ताकि नए भवनों का निर्माण शुरू किया जा सके।

इन दोनों परिसरों में पांच दशक से भी अधिक समय से महत्वपूर्ण मंत्रालय और कार्यालय संचालित होते रहे हैं। इनमें प्रधान महानिदेशक (सूचना) का कार्यालय तथा शिक्षा, सूचना एवं प्रसारण, महिला एवं बाल विकास,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'वंदे मातरम् के सभी अंतरे नहीं गाने पर दंडित नहीं किया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वास्तविक आधार पर धार्मिक आपत्ति रखने वालों को इसके विवादित अंतरे नहीं गाने पर दंडित नहीं किया जाए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि भले ही 'वंदे मातरम्' राष्ट्रीय गीत बना हुआ है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत, अगर किसी को वास्तविक धार्मिक आपत्ति है तो उसे इसके विवादित अंतरों को न गाने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता।

- सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने यह आदेश कर्नाटकी संगीत के जाने-माने संगीतकार टी.एम. कृष्णा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। कृष्णा ने केन्द्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें वंदे मातरम् के सभी 6 अंतरे गाना अनिवार्य किया गया था तथा ऐसा नहीं करने पर दंड का प्रावधान था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की बैंच कर्नाटक संगीतकार टी. एम. कृष्णा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कृष्णा ने केन्द्र के उस सर्कुलर को चुनौती दी है, जिसमें वंदे मातरम् के सभी छह अंतरों को गाना अनिवार्य किया गया है और एक संशोधन के जरिए, इस गीत को राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री आज जैतारण व रामदेवरा जाएंगे

जयपुर, 22 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जैतारण एवं रामदेवरा के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री प्रातः जयपुर से रवाना होकर दोपहर 12:05 बजे जैतारण पहुंचेंगे। इसके बाद पावन धाम, जैतारण में 'सेवा

- जैतारण में "सेवा संकल्प बाइक रैली" के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में तथा रामदेवरा में पदयात्रा में शामिल होंगे।

संकल्प बाइक रैली' के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में शामिल होंगे।

दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक मुख्यमंत्री पावन धाम परिसर में समाधि दर्शन, जनसभा तथा युवाओं के साथ संवाद करेंगे।

दोपहर बाद लगभग 3:20 बजे मुख्यमंत्री रामदेवरा में बाबा रामदेव पैनोरमा जाएंगे। यहां वे पैनोरमा से मुख्य बाजार होते हुए बाबा रामदेव मंदिर तक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान के दोस्त टर्की ने डीज़ल के लिए भारत का रूख किया

असल में टर्की को रूस से पर्याप्त मात्रा में डीज़ल नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने भारत से डीज़ल खरीदना शुरु किया है तथा अगस्त में रिकॉर्ड मात्रा में डीज़ल खरीदा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। पाकिस्तान के प्रमुख रणनीतिक सहयोगी तुर्किये ने अगस्त 2026 में भारत से रिकॉर्ड मात्रा में डीज़ल आयात किया, जो पिछले कई सालों में नई दिल्ली से की गई उसकी सबसे अधिक खरीद है। रूस से सप्लाई में कमी और मध्य पूर्व के रास्तों में रूकावट के कारण राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के नेतृत्व वाले तुर्किए के लिए भारत ईंधन का एक अहम विकल्प बनकर उभरा है।

तुर्किये ऐसे समय में डीज़ल के लिए भारत का रुख कर रहा है, जब उसका पारंपरिक ईंधन आपूर्तिकर्ता रूस अब पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पा रहा है।

- हाल ही में टर्की पाकिस्तान के सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी के रूप में उभरा है। उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था।
- यही नहीं, टर्की ने पाकिस्तान व सऊदी अरब के साथ मिलकर नाटो जैसा संगठन, "मक्का डिफैंस अलायंस" बनाया है, जिसके तहत एक देश पर हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा।
- टर्की पहले भी भारत से डीज़ल खरीदता था, पर, इस क्षेत्र में रूस व मिस्र के बाद भारत का नम्बर तीसरा था।

अगस्त में तुर्किये द्वारा भारत से डीज़ल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि रूस से आपूर्ति में तेजी से गिरावट आई। इसके कारण पाकिस्तान के इस सहयोगी देश को अपने पारंपरिक रूसी सप्लायर के अलावा, अन्य जगहों से ईंधन तलाशने पर मजबूर होना पड़ा।

तुर्किये पाकिस्तान के सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगियों में से एक बनकर उभरा है और उसने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद का मजबूती से समर्थन किया था। राष्ट्रपति एर्दोगन के नेतृत्व वाले तुर्किये ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मिलकर नाटो जैसी रणनीतिक रक्षा साझेदारी भी बनाई है, जिसका नाम "मक्का डिफेंस अलायंस" है।

फिर भी, ग्लोबल ऑयल सप्लाई में व्यापक व्यवधान के बीच तुर्किये के खरीदार अब भारतीय रिफाइनरियों से रिकॉर्ड मात्रा में डीज़ल खरीद रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि यह बदलाव कितना जबरदस्त रहा है।

कमोडिटी डेटा कंपनी "कैप्लर"

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एडवोकेट रस्तोगी को दी गई धमकी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया

जयपुर, 22 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने शहर के गोपालपुरा बाईपास पर कोचिंग सेंटरों के संचालन से जुड़े मामले में सीनियर एडवोकेट आरडी रस्तोगी को कोचिंग सेंटर मालिक द्वारा धमकी दिए जाने को गंभीरता से लिया

- डीजीपी को मामले में सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

है। अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वे मामले में सख्त कार्रवाई करें।

सुनवाई के दौरान, पूर्व सॉलिसिटर जनरल व सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार सहित कई सीनियर एडवोकेट उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि एक कोचिंग सेंटर के मालिक रघुवीर सिंह डागुर ने सीनियर एडवोकेट आरडी रस्तोगी सहित, 10-बी स्कीम विकास समिति के अध्यक्ष एडवोकेट वीरेन्द्र अग्रवाल और महासचिव गोपाल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या यूएन जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी गंभीर मंत्रणा पर फोकस कम हो रहा है

इसके बजाय एक-दूसरे को मैसेज देने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। साल का सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक इवैंट न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा (युनाइटेड नेशन्स की जनरल असैम्बली) के साथ शुरू होने जा रहा है, जिसे संक्षेप में यूएनजीए कहा जाता है। मौजूदा तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र में सुधार की तत्काल जरूरत जैसे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे, जो भारत के लिए बहुत जरूरी हैं, शायद पीछे छूट जाएंगे।

इस साल की यूएनजीए सबसे अधिक विवादित डिप्लोमैटिक इवैंट होगा, क्योंकि जनरल असैम्बली में कई गंभीर मुद्दे चर्चा के लिए सामने आएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अपने युद्ध को सही ठहराने की कोशिश करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति अपने देश में अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना करेंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस की ओर से की गई बिना उकसावे की आक्रामकता की बात करेंगे और इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास के खिलाफ इज़रायल के हमले पर अपना पक्ष रखेंगे।

इसी बीच सबसे बड़ा अनकहा डर यूरोप में एक विनाशकारी युद्ध का है। यह युद्ध यूक्रेन युद्ध के विस्तार के रूप में पश्चिमी यूरोपीय देशों और रूस के बीच हो सकता है। इस समय रूस यूरोप में नाटो सदस्य देशों को ऐसे जानबूझकर किए जा रहे तोड़फोड़ के कामों के जरिए उकसा रहा है, जिनका सीधा संबंध रूस से साबित नहीं किया जा सकता।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस बैठक में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं और उनकी डॉनल्ड

- न्यूयॉर्क में युनाइटेड नेशन्स की जनरल असैम्बली की बैठक होने जा रही है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि, वे अमेरिका जाएंगे, लेकिन वे सीधे वॉशिंगटन जाएंगे और ट्रंप द्वारा आयोजित भव्य रात्रिभोज में शामिल होंगे।
- यूएन की जनरल असैम्बली की मीटिंग में शी जिनपिंग की अनुपस्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे नई दिल्ली में जी-20 की मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल नहीं हुए थे। अफवाह थी कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वे बीजिंग लौट गए थे।

ट्रंप के साथ आमने-सामने की बैठक होनी है। मैक्रों यूरोप की सुरक्षा के लिए बढ़ते रूसी खतरे का लगातार जिक्र करते रहे हैं। नाटो और यूरोप की सुरक्षा को लेकर डॉनल्ड ट्रंप के विचारों को लेकर अक्सर उनकी ट्रंप से तनातनी होती रही है।

लेकिन सबसे बड़ा तनाव मध्य पूर्व में चल रहे टकराव को लेकर पैदा होगा, जो अब लगभग बेकाबू होता जा रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस सहित, कई अरब देशों के नेता डॉनल्ड ट्रंप से मिलकर ईरान के खतरे को रोकने की रणनीति बनाने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव के परिणामस्वरूप, अरब देशों को ईरान की ओर से भारी हमलों का सामना करना पड़ रहा है।

यूएनजीए में शामिल होने के लिए अमेरिका रवाना होने से पहले ही ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका के खिलाफ अपने तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बिना उकसावे के युद्ध शुरू करने और ईरान की आम नागरिक आबादी पर भयंकर हमले करने के लिए अमेरिका की आलोचना की है।

राष्ट्रपति पेज़ेशकियन और ईरान के अधिकारियों ने बार-बार देश में अमेरिका की ओर से किए गए उस बमबारी अभियान का उल्लेख किया है, जिसमें एक स्कूल भी निशाना बना था। इस बमबारी में 150 से अधिक स्कूली बच्चों की मौत हुई थी और इसे युद्ध अपराध बताया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस घटना पर न तो माफी मांगी है और न ही खेद जताया है।

अमेरिकी धरती पर कदम रखने से पहले ही इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक बड़े विवाद के केन्द्र में आ गए हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की अपनी मांग दोहराई है। ममदानी नेतन्याहू को हमास के खिलाफ उनकी सैन्य कार्रवाई के लिए युद्ध अपराधी मानते हैं। इस कार्रवाई में कथित तौर पर 75,000

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राष्ट्रपति ने अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया

नई दिल्ली, 22 सितंबर। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और उनकी उत्कृष्ट सिनेमाई यात्रा के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित

- अभिनेता अनंत नाग ने इस पुरस्कार को उनके साथ काम करने वाले कलाकारों व तकनीशियनों को समर्पित किया।

किया गया। गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समक्ष) में मंगलवार को आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया।

अनंत नाग को यह पुरस्कार उनकी पांच दशकों से अधिक लंबी शानदार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)